जलांश

खंड -6 अंक -07

फरवरी -2024

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

श्री कुशविंदर वोहरा
अध्यक्ष, के ज आ

संदेश

2024 की शुरुआत के साथ, हमारा देश जल प्रबंधन के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत आने वाले वर्षों में जल सुरक्षा के प्रतीक के रूप में उभरेगा।

इसके अलावा, 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, आइए हम अपने संविधान में निहित सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराएँ और सभी के लिए एक उज्जवल और अधिक समावेशी भविष्य के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करें।

जल विजन @2047-वे अहेड पर 'अखिल भारतीय सचिव सम्मेलन' जनवरी, 2024 के अंतिम सप्ताह में महाबलीपुरम, चेन्नई (तमिलनाडु) में आयोजित किया गया था। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में 30 सचिवों और 300 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य हमारे देश की जल सुरक्षा को मजबूत करना है।

प्रतिभागियों ने जनवरी 2023 को भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित "जल पर प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री सम्मेलन" के दौरान रखी गई सिफारिशों के जवाब में की गई कार्यवाई और अमूल्य अंतर्दृष्टि को साझा किया। के.ज.आ. ने आयोजन की संरचना में प्रमुख भूमिका निभाई। मैंने जल संसाधन से जुड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ एक सत्र आयोजित किया ताकि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में उनके दृष्टिकोण और तैयारियों को समझा जा सके। जल संसाधन क्षेत्र हमारे देश को एक विकसित देश बनाने में मुख्य आधार बनने जा रहा है।

एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने "संशोधित पारबती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) -पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी)" की डीपीआर तैयार करने के लिए 28.01.2024 को नई दिल्ली में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस प्रक्रिया में के.ज.आ. ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

हम चल रही पीएमकेएसवाई एआईबीपी परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।जनवरी, 2024 के दौरान आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मणिपुर राज्यों की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। कई परियोजनाओं की बाधाओं को दूर करने और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए आगे का रास्ता तय किया गया।

हितधारकों के साथ बातचीत करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, ओडिशा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों के साथ तीसरी तिमाही वार्ता बुलाई गई। इन संवादों ने केंद्रीय जल आयोग और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन/सिंचाई/जल शक्ति विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। खुले संचार और साझा अंतर्दृष्टि के माध्यम से, हमारा लक्ष्य कुशल जल प्रबंधन और सतत विकास की दिशा में हमारे सामूहिक प्रयासों को मजबूत करना है।

माह के दौरान मेरी बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ रचनात्मक बैठक हुई। जहां हमने राज्य में जल संसाधन परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। हमारी चर्चाओं में डीआरआईपी-III में बिहार परियोजनाओं को शामिल करने, कोसी-मेची परियोजना का मूल्यांकन, पीएफआर-बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना (बीआईडब्ल्यूआरएमपी) और "बाएं कमला बलान तटबंध और दाएं कमला तटबंध चरण- I और II के उत्थान, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण" के लिए निवेश मंजूरी से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे। हमने बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव को इन मामलों में अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन देने का आश्वासन दिया।

के.ज.आ. हितधारकों की जरूरतों के अनुरूप खुद को फिर से उन्मुख करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। ऐसा करते समय हम ऐसे परिवर्तनों को पूरा करने और भविष्य में आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के मामले में पूरी तरह से तैयार हैं।

विषयसूची

परियोजनाओं के संबंध में बैठकें

- लखवार एमपीपी, उत्तराखंड
- रेणुकाजी बांध परियोजना, हिमाचल प्रदेश
- जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तराखंड
- पुनात्सांगछू-I एचईपी, भूटान के लिए 33वीं टीसीसी बैठक
- राजस्थान में नोहर फीडर और बरूवाली वितरिका
-
- उत्तरी कोयल परियोजना, बिहार और झारखंड के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए टीईसी की 33वीं बैठक

वेबिनार/कार्यशाला/प्रशिक्षण

- जनवरी-2024 के दौरान एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा प्रशिक्षण गतिविधि

दौरा/निरीक्षण

- फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी)

एनडीएसए और डीआरआईपी

- डीआरआईपी-II की मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) और डीआरआईपी-III का प्रारंभिक मिशन

के.ज.आ. की अन्य गतिविधियाँ

- राज्यों के साथ तीसरी त्रैमासिक वार्ता बैठक

अन्य गतिविधियाँ

1. अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के साथ बैठक
2. जल विजन @2047 पर अखिल भारतीय सचिव सम्मेलन
3. फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी)
4. आईआईटी रूड़की में अंतर्राष्ट्रीय बांध उत्कृष्टता केंद्र (आईसीईडी) के सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक
5. सीएसएमआरएस की 38वीं स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति (एसटीएसी) बैठक
6. राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उप-समिति 08 राज्यों आन्ध्रप्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश से प्राप्त "सूखा शमन परियोजना" के प्रस्ताव पर विचार करेगी

- पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी एवं डब्ल्यूएम
- पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं के लिए स्क्रीनिंग समिति की 5वीं बैठक
- चल रही पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं की समीक्षा के लिए समिति की बैठक

जलाशय निगरानी

परियोजनाओं के संबंध में बैठकें

लखवार एमपीपी, उत्तराखंड

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 31.01.2024 को लखवार एमपीपी, उत्तराखंड पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। के.ज.आ., यूजेवीएनएल और एलएंडटी के अधिकारियों ने कर्तन क्षेत्र उपचार पद्धति और कर्तन क्षेत्र उपचार के अनुक्रम पर चर्चा करने के लिए बैठक में भाग लिया।

रेणुकाजी बांध परियोजना, हिमाचल प्रदेश

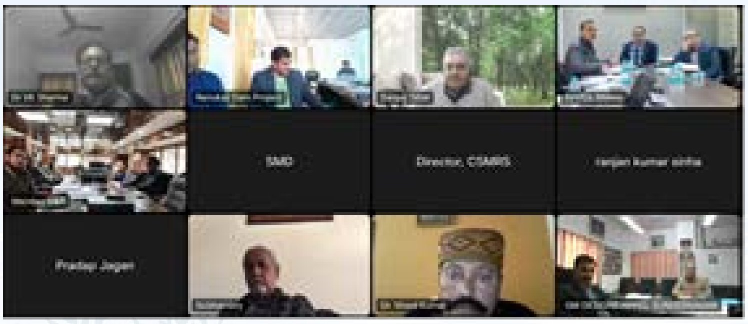

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने रेणुकाजी बांध परियोजना, एचपी से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए रेणुकाजी बांध परियोजना के भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों के पैनल, के.ज.आ., सीएसएमआरएस, जीएसआई और एचपीपीसीएल के अधिकारियों के साथ 04.01.2024 को वीसी के माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता की ताकि निविदा चरण डिजाइन और ड्राइंग कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए रेणुकाजी बांध स्थल में चल रहे जांच कार्यों की स्थिति की समीक्षा की जा सके।

जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तराखंड

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 24.01.2024 को जमरानी बहुउद्देश्यीय परियोजना, उत्तराखंड के लिए कंक्रीट लगाने/बांध के प्रकार के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के मुद्दे की जांच के लिए समीक्षा समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री विवेक त्रिपाठी मुख्य अभियंता, डिज़ाइन (एन एंड डब्ल्यू), श्री एस.डी.शर्मा, मुख्य अभियंता, डिजाइन (ई एंड एनई) और के.ज.आ., सीएसएमआरएस और यूपीडीसीसी-पीआईयू जमरानी, उत्तराखंड सरकार के अन्य अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। उत्तराखंड राज्य के अधिकारियों ने फ्लाई-ऐश परीक्षण रिपोर्ट, गतिशील विश्लेषण और समीक्षा लागत अनुमान पर प्रस्तुति दी। समिति ने विचार-विमर्श के दौरान उपयोग किए जाने वाले कंक्रीट के प्रकार के संबंध में निर्णय लिया और परियोजना अधिकारियों को इसके मिश्रित डिजाइन को अंतिम रूप देने की सलाह दी।

पुनात्सांगछू-I एचईपी, भूटान के लिए 33वीं टीसीसी बैठक

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. और सह-अध्यक्ष-टीसीसी ने श्री एम.ए.के.पी. सिंह, सदस्य (हाइड्रो), सीईए और अध्यक्ष-टीसीसी के साथ 05.01.2024 को हाइब्रिड मोड में पुनातसांगचू-I एचईपी, भूटान के लिए आयोजित 33वीं टीसीसी बैठक की अध्यक्षता की। दाशो छेवांग रिनज़िन, एमडी (डीजीपीसी), दाशो येशी वांगडी, पूर्व विद्युत सचिव, श्री कर्मा पी दोरजी, निदेशक,

ऊर्जा विभाग (एमओईएनआर), टीसीसी के सदस्य और आरजीओबी/ एमईए/ डीएचपीएस/ पीएचपीए-/ सीईए/ के.ज.आ./ डब्ल्यूएपीसीओएस के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। 33वीं टीसीसी बैठक पिछली दो टीसीसी बैठकों की निरंतरता में ही थी और मुख्य रूप से पिछली दो टीसीसी बैठकों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने के लिए थी जिसमें परियोजना की भू-तकनीकी जांच की अद्यतन स्थिति शामिल थी।

राजस्थान में नोहर फीडर और बरूवाली वितरिका

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 31.01.2024 को नोहर फीडर और बरूवाली वितरिका से राजस्थान में पानी की कम उपलब्धता के मुद्दे के संबंध में के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा द्वारा ली गई बैठक में भाग लिया। यह बैठक हरियाणा और राजस्थान को लाभान्वित करने वाली नोहर फीडर और बरूवाली वितरिका के पीएफआर से संबंधित मुद्दों के संबंध में पहले आयोजित बैठकों की श्रृंखला को जारी रखते हुए आयोजित की गई थी। बैठक में के.ज.आ. के अधिकारी, डब्ल्यूआरडी, राजस्थान, आईएंडडब्ल्यूआरडी, हरियाणा और बीबीएमबी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। चर्चा के बाद, लागत साझा करने के सिद्धांतों, पीएफआर में शामिल किए जाने वाले कार्यों और तौर-तरीकों पर हरियाणा और राजस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई। अध्यक्ष, के.ज.आ. ने निर्देश दिया कि प्रस्ताव के लिए पीएफआर डब्ल्यूआरडी, राजस्थान द्वारा अनुमोदन हेतु के.ज.आ. को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा। अध्यक्ष, के.ज.आ. ने इस परियोजना में आगे बढ़ने पर सहमति के लिए दोनों राज्यों को बधाई दी।

उत्तरी कोयल परियोजना, बिहार और झारखंड के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए टीईसी की 33वीं बैठक

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना (एनकेपी) के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की 33वीं बैठक 11.01.2024 को सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. और अध्यक्ष (टीईसी), एनकेपी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में जल संसाधन विभाग, के.ज.आ. मुख्यालय एवं क्षेत्रीय इकाइयों, बिहार, झारखंड राज्य सरकारों और वैपकोस के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा हुई जैसे डब्ल्यूआरडी बिहार/ झारखंड द्वारा भूमि अधिग्रहण की स्थिति, वैपकोस द्वारा परियोजना के शेष कार्यों के विभिन्न घटकों की प्रगति, वैपकोस द्वारा बिहार में आरडी 68.37 से 109.09 किमी तक आरएमसी और इसकी संरचनाओं की लाइनिंग मरम्मत और निर्माण कार्य के लिए निविदा दस्तावेज पर विचार, झारखंड सरकार और वैपकोस के पास खर्च न की गई शेष बची राशि की स्थिति आदि।

वेबिनार/कार्यशाला/प्रशिक्षण

जनवरी-2024 के दौरान एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा प्रशिक्षण गतिविधि

1. सतही जल संसाधनों और उनके प्रबंधन का अवलोकन

1 से 5 जनवरी 2024 तक सीजीडब्ल्यूबी के नवनियुक्त समूह-ए अधिकारियों के लिए "सतही जल संसाधनों और उनके प्रबंधन का अवलोकन" पर एक अनुकूलित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य जल शक्ति मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ाना, क्षेत्रीय जल चुनौतियों को सामूहिक रूप से संबोधित करने के लिए एक मंच तैयार करना है।

प्रशिक्षण मॉड्यूल विशेष रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड अधिकारियों के लिए सतही जल प्रबंधन पर केंद्रित था। इसमें जल संसाधन क्षेत्र में रणनीतिक मुद्दे, भारत में डब्ल्यूआरडीएम के लिए कानूनी ढांचा, हाइड्रोलॉजिकल अवलोकन और बाढ़ पूर्वानुमान, आईडब्ल्यूआरएम और डब्ल्यूक्यू निगरानी जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया गया। इस व्यापक दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रभावी जल क्षेत्र प्रबंधन के लिए अधिकारियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना, राज्य-विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने और व्यवहार्य समाधान खोजने में सहयोगात्मक प्रयासों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना है।

2. पंप भंडारण जलविद्युत परियोजना

"पंप भंडारण जलविद्युत परियोजना " पर एक व्यापक 5-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 8 से 12 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए), के.ज.आ., पुणे में शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को पंप स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं की योजना और विकास, भारत की भविष्य की ऊर्जा मांगों को पूरा करने हेतु उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने में शामिल बहुमुखी पहलुओं की गहन समझ से लैस करना है।

कार्यक्रम में विभिन्न राज्य और केंद्र सरकारों के 49 प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई, जो पंप स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं के क्षेत्र में ज्ञान, सहयोग और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक सामूहिक प्रयास का प्रतीक है।

3. जल संसाधन प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली अनुप्रयोग

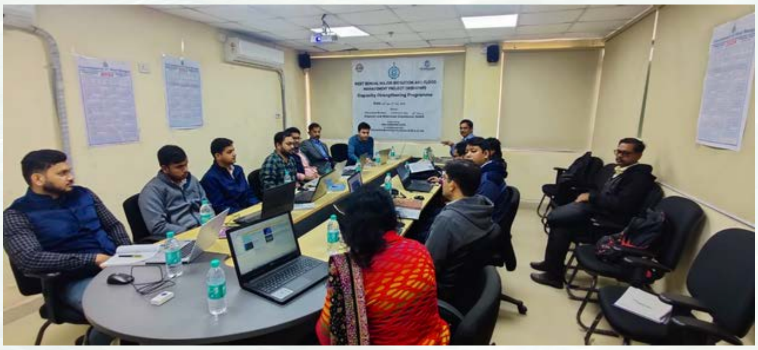

राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए) ने एसपीएमयू-पश्चिम बंगाल वृहत सिंचाई और खाद्य प्रबंधन परियोजना (डब्ल्यूबीएमआईएफएमपी),सिंचाई और जलमार्ग विभाग (आई एंड डब्ल्यूडी), पश्चिम बंगाल सरकार (जीओडब्ल्यूबी) के अधिकारियों के लिए जलसम्पदा भवन, कोलकाता में 29 जनवरी 2024 से 02 फरवरी 2024 तक "जल संसाधन प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली अनुप्रयोगों" पर पांच दिवसीय अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

पश्चिम बंगाल वृहत सिंचाई और खाद्य प्रबंधन परियोजना (डब्ल्यूबीएमआईएफएमपी) को सिंचाई और जलमार्ग विभाग(आई एंड डब्ल्यूडी), पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दामोदर घाटी कमान क्षेत्र (डीवीसीए) के 5 जिलों (पूर्व और पश्चिम बर्धमान, हावड़ा, बांकुरा और हुगली) में विश्व बैंक और एशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वित्तीय सहयोग से लागू किया गया था, ताकि सिंचाई सेवाओं में सुधार किया जा सके और वार्षिक बाढ़ के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाई जा सके, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सके।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को भू-स्थानिक डेटासेट विश्लेषण, बेसिन/ कमांड स्केल का समर्थन, अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेने के लिए मुफ्त और ओपनसोर्स सॉफ़्टवेयर टूल और प्लेटफ़ॉर्म की एक श्रृंखला से परिचित कराना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डब्ल्यूबीएमआईएफएमपी/आईएंडडब्ल्यूडी, पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न ग्रेड के अधिकारियों सहित पंद्रह प्रतिभागियों ने भाग लिया। कवर किए गए विषयों में आरएस और जीआईएस की अवधारणाएं सहित, ओपन एक्सेस सैटेलाइट इमेजरी और डेटा स्रोत; जलग्रहण परिसीमन सहित डीईएम का हाइड्रो प्रसंस्करण; समय श्रृंखला विश्लेषण और परिवर्तन का पता लगाना; बाढ़ मानचित्रण और निगरानी; सूखे की निगरानी; जल निकायों का निष्कर्षण और मानचित्रण; अर्ध-पर्यवेक्षित भूमि कवर वर्गीकरण; सिंचाई जल प्रबंधन - ईटी विश्लेषण; जीईई ऐप्स बनाना और प्रयोग करना; पायथन आदि के साथ क्यूजीआईएस को अनुकूलित करना शामिल था। गूगल अर्थ इंजन, एक उपग्रहीय-पैमाने पर भू-स्थानिक विश्लेषण मंच और क्यूजीआईएस का उपयोग व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्रों के लिए किया गया था।

4. बाढ़ सुरक्षा, कटाव निरोधक और नदी प्रशिक्षण कार्यों के लिए डीपीआर तैयार करना

वाल्मी, पटना में "बाढ़ सुरक्षा, कटाव-रोधी और नदी प्रशिक्षण कार्यों के लिए डीपीआर की तैयारी" पर एक व्यापक 5-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय जल अकादमी, के.ज.आ. द्वारा वाल्मी, पटना के सहयोग से डब्ल्यूआरडी, बिहार सरकार के अधिकारियों के लिए किया गया था, जो बाढ़ सुरक्षा, कटाव-रोधी और नदी प्रशिक्षण कार्यों से निपट रहे थे।

प्रशिक्षण पहल का प्राथमिक उद्देश्य प्रतिभागियों को के.ज.आ. के दिशानिर्देशों के अनुपालन में अच्छी तरह से संरचित डीपीआर की सावधानीपूर्वक तैयारी के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना था।

विविध पाठ्यचर्या में बाढ़ प्रबंधन कार्यों के लिए डीपीआर तैयार करने, बाढ़ तटबंधों के डिजाइन पहलू, बैंक रीवेटमेंट, स्पर, जल निकासी सुधार कार्य, लागत अनुमान, बाढ़ प्रबंधन के लिए इकाई दर विश्लेषण, गैर-संरचनात्मक उपाय, एचईसी-आरएएस पर व्यावहारिक अभ्यास, हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययन, बाढ़ प्रबंधन के कानूनी पहलू, जीआईएस का परिचय, और जलग्रहण क्षेत्र के चित्रण पर व्यावहारिक सत्र, समोच्च मानचित्र निर्माण आदि के लिए दिशानिर्देश शामिल थे।

इस कार्यक्रम में एसई, ईई और एईई स्तर के जल संसाधन विभाग के तीस अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

दौरा/निरीक्षण

फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी)

श्री एस.डी.शर्मा, सीई डिजाइन (ई एंड एनई), श्री एस.के.शर्मा, निदेशक, बीसीडी (ई एंड एनई) और के.ज.आ. के अन्य अधिकारियों ने नहर अध्ययन समूह (सीएसजी) के लिए फरक्का बैराज परियोजना का दौरा किया और गेट रेगुलेशन कमेटी (जीआरसी) की बैठक में भाग लिया जो 2 और 3 जनवरी,2024 को फरक्का बैराज परियोजना, फरक्का के समिति कक्ष में आयोजित की गई थी।

एनडीएसए और डीआरआईपी

डीआरआईपी-II की मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) और डीआरआईपी-III का प्रारंभिक मिशन

डीआरआईपी-II और डीआरआईपी-III के प्रारंभिक मिशन के लिए मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) 18 से 20 जनवरी 2024 के दौरान भुवनेश्वर, ओडिशा में और 29 से 31 जनवरी 2024 को सूरत, गुजरात में आयोजित की गई थी। जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, विश्व बैंक और आठ कार्यान्वयन एजेंसियों (मणिपुर, मेघालय, यूजेवीएनएल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और डीवीसी) के अधिकारियों ने भुवनेश्वर में एमटीआर में भाग लिया। और बारह कार्यान्वयन एजेंसियों (केरल डब्ल्यूआरडी, केरल एसईबी, कर्नाटक, एपी, गुजरात, राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु (डब्ल्यूआरडी और टैंजेडको); बीबीएमबी, छत्तीसगढ़, यूपी) ने सूरत में आयोजित एमटीआर में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान, डीएसआर निदेशालय के निदेशक श्री एस.एस.बख्शी ने डीआरआईपी चरण II की समग्र प्रगति पर एक प्रस्तुति दी। इसके बाद, सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा योजना के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली समस्याओं के साथ-साथ

भौतिक और वित्तीय प्रगति पर प्रकाश डालते हुए प्रस्तुतियां भी दी गईं। इसके अलावा, पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) अनुपालन पर सभी आईए को संवेदनशील बनाने के लिए, एमटीआर के समानांतर पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं पर एक दिवसीय सत्र आयोजित किया गया था।

के.ज.आ. की अन्य गतिविधियाँ

1. राज्यों के साथ तीसरी त्रैमासिक वार्ता बैठक

के.ज.आ. ने जल संसाधनों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में के.ज.आ. द्वारा किए जा रहे कार्यों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए कार्यों में तालमेल बढ़ाने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन/सिंचाई/जल शक्ति विभाग के साथ बातचीत शुरू की है। तीसरे त्रैमासिक संवाद निम्नलिखित विवरण के अनुसार आयोजित किए गए थे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

एनसीटी दिल्ली सरकार और के.ज.आ. और सीजीडब्ल्यूबी के अधिकारियों के बीच तीसरी त्रैमासिक वार्ता 05.01.2024 को श्री जी.के. अग्रवाल, मुख्य अभियंता, यमुना बेसिन संगठन की अध्यक्षता में कालिंदी भवन, वाईबीओ, के.ज.आ., नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान दिल्ली में यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता और एनसीटी दिल्ली के दक्षिण और दक्षिण-पूर्व जिलों में भूजल प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

ओडिशा

तीसरी त्रैमासिक वार्ता 25.01.2024 को एम एंड ईआरओ, के.ज.आ., भुवनेश्वर के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी। के.ज.आ., भुवनेश्वर, सीजीडब्ल्यूबी, भुवनेश्वर और डब्ल्यूआरडी, ओडिशा के विभिन्न अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया और आरआरआर परियोजनाओं, नए बाढ़ पूर्वानुमान स्थलों को शामिल करने के संबंध में चर्चा की गई।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल राज्य के साथ तीसरी त्रैमासिक वार्ता बैठक 03.01.2024 को सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग के सचिव, श्री संजय कुंडू की अध्यक्षता में जलसंपद भवन में आयोजित की गई थी। बैठक में सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग, जल संसाधन जांच एवं विकास निदेशालय और राज्य जल जांच विभाग और सीजीडब्ल्यूबी, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता के अधिकारियों ने भाग लिया।

भारत-बांग्लादेश संधि 1996 की समीक्षा के लिए राज्य द्वारा आवश्यक भागीरथी और इचामती नदियों पर जल गुणवत्ता पहलुओं, के.ज.आ., कोलकाता द्वारा जारी बाढ़ पूर्वानुमान, तीस्ता परियोजना, संभावित एसएमआई परियोजनाओं और पश्चिम बंगाल में आरआरआर परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। एक स्वस्थ और उपयोगी विचार-विमर्श किया गया। पश्चिम बंगाल राज्य के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों ने के.ज.आ. द्वारा की गई पहल की सराहना की है।

2. अन्य गतिविधियाँ

अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के साथ बैठक

श्री चैतन्य प्रसाद, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, सरकार। बिहार सरकार ने 01.01.2024 को श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग और पदेन सचिव, भारत सरकार से उनके कार्यालय में मुलाकात की।

डीआरआईपी-III में बिहार की परियोजनाओं को शामिल करने, कोसी-मेची परियोजना का मूल्यांकन, पीएफआर-बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना (बीआईडब्ल्यूआरएमपी), "बाएं कमला बलान तटबंध और दाएं कमला तटबंध चरण- I और II के उत्थान, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण" की निवेश मंजूरी आदि सहित बिहार सरकार के कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने इस मामले में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

जल विजन @2047 पर अखिल भारतीय सचिव सम्मेलन

के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा ने 24.01.24 को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 'जल विजन @ 2047 पर अखिल भारतीय सचिव सम्मेलन' के दौरान जल के क्षेत्र में काम करने वाली विभिन्न कंपनियों और नई कंपनियों के सीईओ के साथ "एक गोलमेज सम्मेलन" आयोजित किया। सचिव, डी ओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर ने 24.01.2024 को आयोजित गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों और सीईओ द्वारा समान रूप से उत्साहपूर्ण भागीदारी और बातचीत देखी गई; मूल्यवान विवरण और अंतर्दृष्टि का आदान-प्रदान किया गया। नवाचारों, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग आदि के क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भूमिका पर विधिवत प्रकाश डाला गया। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, जल क्षेत्र में नवाचारों, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग आदि के क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भूमिका पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया, क्योंकि वे न केवल सरकारी एजेंसियों को, बल्कि किसानों और अन्य हितधारकों को भी उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं ।

सम्मेलन को विज़न 2047 के अनुरूप भारत को एक जल-सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए आगे के रास्ते पर चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने के लिए सभी संबंधित लोगों के साथ सहयोग को बढ़ावा देकर एक और कदम के रूप में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था।

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने बैठक के दौरान उभरे विभिन्न उपयोगी बिंदुओं का अवलोकन करते हुए सत्र का समापन किया और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी बताया, जो सीईओ द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों में मदद करेंगे।

फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी)

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की 119वीं बैठक की अध्यक्षता की, जो 30 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। फरक्का बैराज परियोजना की टीएसी

का नेतृत्व सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. द्वारा किया जाता है, जो आम तौर पर हर साल एक बार बैठक करता है और परियोजना के कुशल और सुरक्षित कामकाज के लिए निष्पादित किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में निर्णय लेता है। 119वीं टीएसी बैठक में, सदस्य (डी एंड आर) ने फरक्का बैराज परियोजना अधिकारियों के साथ विभिन्न समस्याओं, विशेष अध्ययनों और संबंधित डिजाइन कार्यों के संबंध में चर्चा की, जिन्हें डी एंड आर विंग को भेजा गया था।

आईआईटी रूड़की में अंतर्राष्ट्रीय बांध उत्कृष्टता केंद्र (आईसीईडी) के सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 16.01.2024 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में आईआईटी रूड़की में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय बांध उत्कृष्टता केंद्र (आईसीईडी) के सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक में भाग लिया। आईआईटी रूड़की में बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (आईसीईडी) की स्थापना के लिए के.ज.आ. और आईआईटी रूड़की के बीच 14.02.2023 को एमओए पर हस्ताक्षर किए गए। इस संबंध में, आईआईटी रूड़की में स्थापित बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (आईसीईडी) के सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक जल शक्ति मंत्रालय के सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान आईसीईडी की भौतिक और वित्तीय प्रगति के संबंध में विचार-विमर्श किया गया, जिसमें एमओए के अनुसार आईसीईडी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट की स्थिति, एमओए पर हस्ताक्षर करने के बाद से पहले वर्ष के लिए डिलिवरेबल्स और संबंधित समयसीमा, आईसीईडी द्वारा खरीद, आईसीईडी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशालाएं आदि शामिल हैं।

सीएसएमआरएस की 38वीं स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति (एसटीएसी) बैठक

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने सीएसएमआरएस की 38वीं स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति (एसटीएसी) की बैठक की अध्यक्षता की, जो 29.01.2024 को कॉन्फ्रेंस रूम, तीसरी मंजिल, के.ज.आ. में आयोजित की गई थी।

सीएसएमआरएस में शुरू की जा रही अनुसंधान योजनाओं की तकनीकी जांच में समग्र परिप्रेक्ष्य और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति (एसटीएसी) का गठन किया गया था। एसटीएसी विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों से लिए गए 11 सदस्यों से बना है और इसका नेतृत्व सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. द्वारा किया गया। चर्चा किए गए विभिन्न एजेंडा बिंदुओं में अक्टूबर से दिसंबर 2023 के दौरान भौतिक उपलब्धियां, तकनीकी रिपोर्ट, शोध पत्र, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का तकनीकी मूल्यांकन, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से संबंधित गतिविधियां, सीएसएमआरएस द्वारा आयोजित प्रशिक्षण, वित्तीय उपलब्धियां, सीएसएमआरएस के कर्मचारियों की स्थिति आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उप-समिति 08 राज्यों आन्ध्रप्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश से प्राप्त "सूखा शमन परियोजना" के प्रस्ताव पर विचार करेगी

08 राज्यों (एपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश) से प्राप्त "सूखा शमन परियोजना" के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उप-समिति की बैठक केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में नॉर्थ ब्लॉक, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में 16 जनवरी 2024 को आयोजित की गई थी। सीडब्ल्यूसी की ओर से मुख्य अभियंता (आईएमओ) और निदेशक (डब्ल्यूएम निदेशालय) ने बैठक में भाग लिया।

जैसा कि पंद्रवी फ़ाइनेंस कमिशन रिपोर्ट की सिफारिश में परिकल्पित है, 08 राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के एजेंडे पर "एनडीएमएफ की फंडिंग विंडो के तहत 'सूखा शमन परियोजना' के लिए विचार विमर्श किया गया।

3. पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी एवं डब्ल्यूएम

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं के लिए स्क्रीनिंग समिति की 5वीं बैठक

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत परियोजनाओं को शामिल करने के लिए स्क्रीनिंग समिति की पांचवीं बैठक सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागकी अध्यक्षता में 05.01.2024 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। के.ज.आ. और महाराष्ट्र सरकार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु, डब्ल्यूआरडी मध्य प्रदेश, एआईबीपी सेल, पुणे, एचपीपीसीएल शिमला के अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान व्यक्तिगत परियोजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में दो परियोजनाओं, अर्थात् महाराष्ट्र राज्य से नीरा देवघर सिंचाई परियोजना और हिमाचल प्रदेश राज्य से फीना सिंह बहुउद्देश्यीय परियोजना को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शामिल करने के लिए चर्चा की गई और पीएमकेएसवाई-एआईबीपी में शामिल करने की सिफारिश की गई, पात्र केंद्रीय सहायता क्रमशः 1392.91 करोड़ रुपये और 282.47 करोड़ रुपये है और निर्धारित समापन तिथि क्रमशः मार्च 2026 और मार्च 2027 है।

चल रही पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं की समीक्षा के लिए समिति की बैठक

वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत शामिल 99 प्राथमिकता वाली (प्रमुख और मध्यम) परियोजनाओं में से चल रही त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम(एआईबीपी)परियोजनाओं की स्थिति और बाधाओं की समीक्षा के लिए मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस प्रयोग के एक हिस्से के रूप में, विभिन्न राज्यों के संबंध में परियोजनाओं की समीक्षा के लिए कई बैठकें आयोजित की गईं।

आंध्र प्रदेश और केरल

आंध्र प्रदेश में सात और केरल में दो चल रही परियोजनाओं की प्रगति की जांच के लिए 20.01.2024 को, सेवा भवन में एक बैठक बुलाई गई थी। प्रतिभागियों में केंद्रीय जल आयोग, राज्य सरकारों के अधिकारी और दोनों राज्यों के आयुक्त और मुख्य अभियंता स्तर के वरिष्ठ अधिकारी थे। समीक्षाधीन परियोजनाओं में कंडुला ओबुला रेड्डी गुंडलाकम्मा जलाशय परियोजना, थोटापल्ली बैराज परियोजना, तारकरमा तीर्थ सागरम परियोजना, मुसुरुमिली जलाशय परियोजना, येराकाल्वा जलाशय परियोजना, पुष्कर लिफ्ट सिंचाई योजना और आंध्र प्रदेश से ताडिपुड़ी लिफ्ट सिंचाई योजना के साथ-साथ केरल की मुवत्तुपुझा घाटी सिंचाई परियोजना (एमवीआईपी) और करापुझा सिंचाई परियोजना शामिल हैं।

प्रत्येक परियोजना की भौतिक बाधाओं के बारे में के.ज.आ. के अध्यक्ष के साथ विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें सिंचाई क्षमता को अधिकतम करने के लिए हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी में कठिनाई उत्पन्न करने वाली बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से कार्यों को प्राथमिकता देने के सुझाव दिए गए। कार्य को समय पर पूरा करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को सिफारिशें प्रदान की गईं। हालाँकि, यह नोट किया गया था कि परियोजना की प्रगति और प्राधिकरण की तैयारियों के कारण, कुछ परियोजनाएँ 31.03.2026 से आगे बढ़ सकती हैं, जिसके लिए फौजदारी उपायों की आवश्यकता होगी।

तेलंगाना और कर्नाटक

29.01.2024 को सेवा भवन, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में तेलंगाना की 05 और कर्नाटक की 01 परियोजना की समीक्षा की गई।

बैठक में केंद्रीय जल आयोग, राज्य सरकारों, मंत्रालय के अधिकारियों और दो राज्य सरकारों के आयुक्तों और मुख्य अभियंताओं के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। समीक्षा के आधार पर, राज्य सरकारों को समय पर परियोजनाओं को पूरा करने और अन्य उचित कार्यों के लिए सुझाव और सलाह दी गई।
कर्नाटक की ऊपरी तुंगा परियोजना की समीक्षा की गई। तेलंगाना की सात परियोजनाओं में से केवल 4 प्रमुख परियोजनाओं, अर्थात् नीलवई जलाशय, जगन्नाथपुर में पेद्दावागु मोड़, इंदिराम्मा बाढ़ प्रवाह नहर और पालेमवागु जलाशय परियोजना की विस्तार से समीक्षा की गई।

तेलंगाना राज्य सरकार के अधिकारियों ने इस बैठक के दौरान जे.चोखा राव एलआईएस परियोजना को स्थगित करने का अनुरोध किया। राजीव भीम एल.आई.एस. और एसआरएसपी स्टेज- ॥ परियोजनाओं के लिए निर्णय तक पहुंचने हेतु तेलंगाना राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी पूरी नहीं है। इसलिए ये तीन (3) परियोजनाएं अर्थात 1. जे. चोखा राव एलआईएस, 2. राजीव भीम एल.आई.एस., 3. एसआरएसपी स्टेज- ॥ परियोजना, अगली समीक्षा बैठक में ली जाएगी।

प्रत्येक परियोजना की विभिन्न भौतिक बाधाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। अध्यक्ष, के.ज.आ. ने कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए विभिन्न सुझाव दिए ताकि अधिकतम सिंचाई क्षमता प्राप्त करने के लिए हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी में रुकावट डालने वाली बाधाओं का समाधान किया जा सके।

कार्यों के निष्पादन की प्रगति और परियोजना प्राधिकरणों की तत्परता ऐसी थी कि इनमें से कुछ परियोजनाएं 31/03/2026 से अधिक का समय ले सकती है और इसलिए इन्हें पुरोबंद करने की आवश्यकता है।

अन्य राज्य

30.01.2024 को आयोजित बैठक में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मणिपुर राज्यों में चल रही पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई।
बैठक में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मणिपुर के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। क्षेत्रीय संगठनों के के.ज.आ. अधिकारियों और नीति आयोग, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागऔर के.ज.आ. मुख्यालय के अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।
बिहार की दो परियोजनाओं पुनपुन और दुर्गावती, असम की बोरोलिया परियोजना, छत्तीसगढ़ की केलो परियोजना, झारखंड की सुवर्णरिखा परियोजना और मणिपुर की थौबल परियोजना के बारे में विस्तार से समीक्षा की गई। बिहार की दो परियोजनाओं के संबंध में और विवरण मांगा गया और इसे अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। बोरोलिया और केलो परियोजनाओं को मार्च, 2026 तक पूरा करने के लिए ठोस प्रयास करने का अनुरोध किया जाएगा। सुवर्णरिखा परियोजना में कई लंबित मुद्दे हैं जिनका समाधान किया जाना है। थौबल परियोजना 2024 के दौरान पूरी हो सकती है।
के.ज.आ. के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि लंबित मुद्दों को हल करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि इन परियोजनाओं में तेजी लाई जा सके।

4. जलाशय निगरानी

के.ज.आ. साप्ताहिक आधार पर देश के 150 जलाशयों की सजीव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 20 जलाशय पनबिजली परियोजनाओं के हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 35.299 बीसीएम है। इन 150 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 178.784 बीसीएम है, जो देश में सृजित अनुमानित भंडारण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 69.35% है।

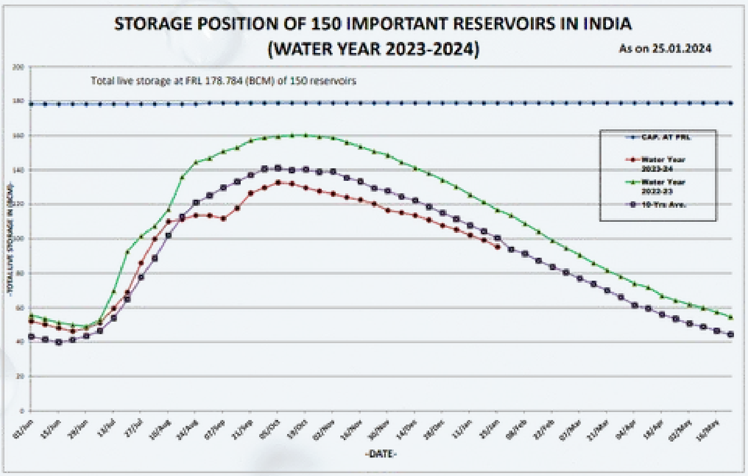

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 25.01.2024 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध भंडारण 95.326 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 53% है। हालाँकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण 116.771 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत संग्रहण 100.481 बीसीएम था। इस प्रकार, 25.01.2024 बुलेटिन के अनुसार 150 जलाशयों में उपलब्ध सजीव भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सजीव भंडारण का 82% और पिछले दस वर्षों के औसत सजीव भंडारण का 95% है।

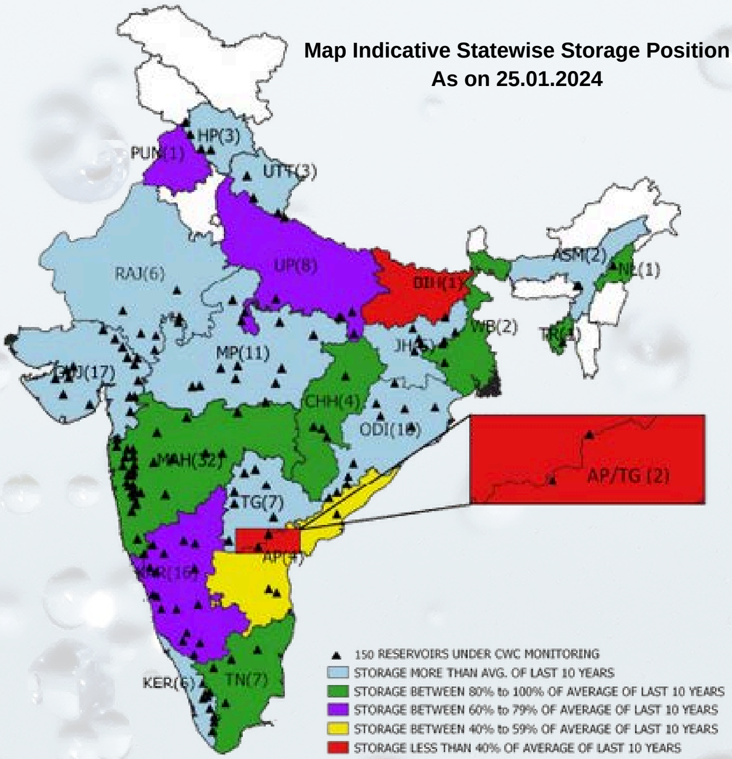

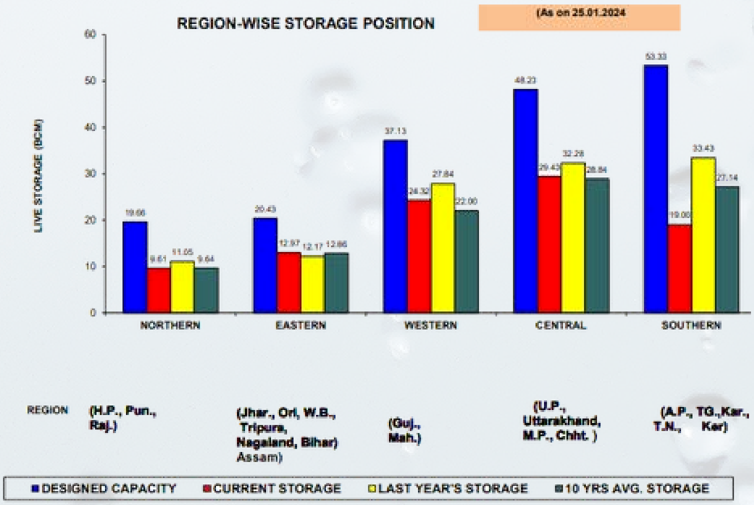

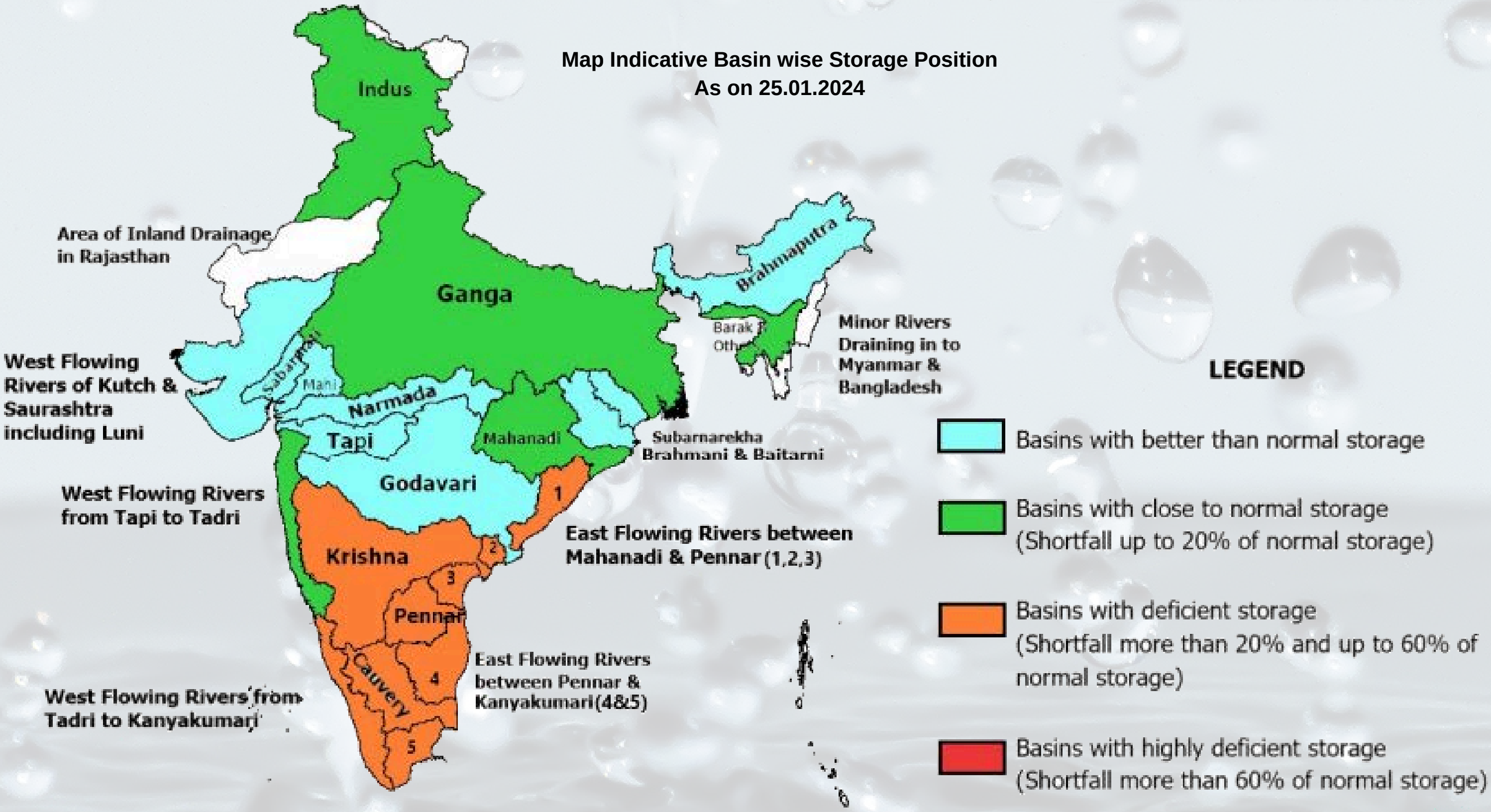

संसदीय राजभाषा समिति ने 15.01.2024 को जयपुर (राजस्थान) में चंबल मंडल, केंद्रीय जल आयोग के साथ निरीक्षण बैठक की। इस दौरान समिति ने मंत्रालय एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हो रहे राजभाषा हिंदी के कार्यों का अवलोकन किया।

एम एंड ईआरओ, के.ज.आ., भुवनेश्वर के तहत साइट अखुआपाड़ा का निरीक्षण श्री पी.एम.स्कॉट, सदस्य (आरएम), सीई, वाईबीओ, एसई, फरीदाबाद और एसई, एचओसी, के.ज.आ., भुवनेश्वर द्वारा 07/01/2024 को किया गया था।

श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, के.ज.आ. और पदेन सचिव, भारत सरकार ने 1 जनवरी, 2024 को 7वीं मंजिल, सेवा भवन, के.ज.आ. (मुख्यालय) में विभागीय कैंटीन का उद्घाटन किया।

गणतंत्र दिवस 26.01.2024 के शुभ अवसर पर के.ज.आ. कार्यालय भवन गांधीनगर में सजावट

केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- डॉ. बी.आर.के. पिल्लै, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री राकेश टोटेजा, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री भूपिंद्र सिंह, निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री सुनीलकुमार -II, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी–सी)- सदस्य
- श्री श्री शेखरेन्दु झा, निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.)-सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in